the Seventh Plan of Doordarshan envisages setting up of a TV programme generation facility centre at Chandigarh. The site for the centre has been selected and orders for major equipment have been placed.

(c) Does not arise.

Target for horticulture coverage

355. SHRI PAWAN KUMAR BANSAL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what is the all India average of area under horticulture;

(b) what is the percentage of such areas in Punjab; and

(c) what is the target fixed for horticulture coverage in the country and what steps have been taken to achieve the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SHYAM LAL YADAV): (a) and (b) As per land utilisation statistics, all-India area under horticultural crops (including fruits and vegetables, condiments and spices, plantation crops and coconut) is estimated about 10 million hectares, constituting about 6 per cent of gross cropped area. In Punjab, about 1.4 per cent of gross cropped area is under horticultural crops.

(c) No targets have been fixed for area coverage under horticultural crops in Seventh Five Year Plan. However, various Central/Centrally sponsored programmes are being implemented during the Seventh Plan for raising the production of horticultural crops.

Steel production in the country

356. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in spite of the finest variety of Iron ore and adequate reserves of coking coal vast reserves of lime stone and dolomite and skilled man-power available in the country, quality Iron is not being produced in the country and the modernisation process is also slow in the steel industry in the country; and

(b) what modernisation programmes are proposed to be adopted by Government for increasing production of steel in the country for self-sufficiency?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STEEL IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b) No Sir, Steel Authority of India Limited is making full use of the appropriate quality of inputs available indigenously for production of quality iron and steel. In addition to having undertaken expansion schemes for Bhilai and Bokaro Steel Plants, a programme for modernisation of the Steel Plants at Durgapur, Rourkela and IISCO are also being taken up for implementation, which apart from upgrading their technology, will also enhance the availability of steel in the country.

दिल्ली में रिहायशी क्षेत्रों में अवैध कारखाने

357. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में भी अवैध रूप से कारखाने चलाए जा रहे हैं तथा इन कारखानों से ऐसी बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के अवैध कारखानों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Payment of minimum wages to women workers

358. PROF. SOURENDRA BHATTACHARJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Governments attention has been drawn to the report of the National Commission on Self-Employed Women in the informal work sector;

(b) whether Government Departments and Undertakings have been defaulters in respect of payment of minimum wages to such working women; and

(c) if so, what steps are being taken to bring the offenders to book?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir. No such complaint has been received by the Central Government.

(c) Does not arise.

आदिवासी क्षेत्रों में चलती-फिरती दुकानें

359. **श्री अजीत जोगी** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पहुंच विहीन आदिवासी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए "चलती फिरती दुकानों" की कोई व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय के समाचार प्राप्त हुए है कि आदिवासी क्षेत्र और जनसंख्या को देखते हुए "चलती-फिरती दुकानों" की संख्या अत्यंत कम है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार इन "चलती फिरती दुकानों" की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजना के प्रशासन तथा कार्यान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की होती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए है, जिनमें उनसे कहा गया है कि वे दुर्गम इलाकों, दुर्गम क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों तथा जिन क्षेत्रों में उचित दर दुकानें नहीं है और जहां उनकी संख्या कम है वहां चलती-फिरती उचित दर की दुकानें चलाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार करें। एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम भी है, जिसके तहत पहाड़ी राज्य क्षेत्रों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के वास्ते चलती-फिरती दुकानें चलाने हेतु वाहन क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1985-86 से 1987-88 के दौरान केन्द्र सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 177 वाहन क्रय करने के लिए 30 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

चार्ल्स कोरिया समिति के सुझावों का कार्यान्वयन

360. **श्री अजीत जोगी** : क्या **विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महानगरीय समस्याओं पर विचार करने के लिए गठित की गई चार्ल्स कोरिया समिति